India Extraordinary. The status of the National Culture Fund has since not undergone any change.

(b) No financial assistance has been extended to the State Governments for the construction of Multi-purpose Cultural Complexes.

Agency to Identify Writers for Nobel Prize in Literature

2258. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any recognised machinery or agency in India to identify eminent writers in various recognised Indian languages for consideration of award of coyeted Nobel prize in literature; and

(b) if not, whether Government would consider setting up of such a machinery or agency?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. Sahitya Academy has been recognised by the Swedish Academy as the nominating body of the Nobel prize in literature.

(b) Does not arise.

M. Tech. courses in NERIST

2259. SHRI NABAM REBIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is fact that M. Tech courses in some disciplines were introduced in the North-Eastern Region Institute of Science and Technology (NERIST) in 1996;

(b) whether it is also a fact that "Deemed University Status" was agreed upon to be conferred upon the said Institute by Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what are the other future plans for the said Institute?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. Post-graduate courses in two disciplines namely Environmental Sciences and Engineering & Information Technology were introduced in NERIST in 1996.

(b) and (c) At the time of establishment of NERIST, it was agreed that in due course the Institute will be conferred with University Status, so that it can award its own Degree and other Qualifications. Steps have been initiated for granting 'deemed university status' to the Institute.

(d) The Institute also proposes to start some more Under-graduate and Post-graduate courses during the 9th Plan.

राष्ट्रीय संग्रहालय जांच समिति के अध्यक्ष का रिक्त पद

2260. प्रो॰ रामगोपाल यादव:
श्री रमा शंकर कौशिक:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय जांच समिति के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है, और यदि हां, तो कब से खाली है;

(ख) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को अध्यक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय संग्रहालय की वस्तुओं की जांच में लापरवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिशा-निर्देशों सहित उच्च-न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय संग्रहालय जांच समिति नाम की कोई समिति नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय संग्रहालय की कला वस्तुओं के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेषज्ञ समिति है। श्री एम॰ एन॰ देसपांडे जो इस समिति के अध्यक्ष थे, गिरते-स्वास्थ्य के कारण अक्तूबर, 1997 से कार्य नहीं कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सरकार को कोई विशेष

निर्देश नहीं दिए हैं। तथापि, न्यायालय ने दिनांक 13.11.1998 के अपने आदेश में आशा व्यक्त की है कि समिति जितनी तेजी से संभव हो, इस कार्य को पूरा करने की स्थिति में होगी, और समिति को निदेश दिया है कि वह दिनांक 28.2.99 तक न्यायालय में मोहरबंद लिफाफे में प्रगति-रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Education of Low Income Family Children in Himachal Pradesh

2261. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that children hailing from low income families in Himachal Pradesh do not complete school education;

(b) if so, whether any survey has been done on this issue;

(c) what are the general finding of the survey; and

(d) in what manner Government propose to ensure that such children complete their schooling?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) As per survey of 6—11 age group children conducted by the Himachal Pradesh Government, 20509 children were not going to school. As per the National Family Health Surevy 1992-93, 90.8% of the defacto household population of age 6 to 14 years were attending school in Himachal Pradesh. As per the 50th Round of National Sample Survey (1993-94), per thousand distribution of Children in the 5 to 14 age group, 86% children in the rural areas and 92.5% children in urban areas were currently attending schools.

(d) Himachal Pradesh has been taken up under the District Primary Education Programme and funds under the scheme of Operation Blackboard are also made available as per guidelines for improving educational facilities.

प्रौढ़ों में व्याप्त निरक्षरता

2262. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रौढ़ों में व्याप्त निरक्षरता को समाप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में प्रौढ़ों में व्याप्त निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने हेतु समय-सीमा के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक निधि भी आंवटित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान वर्ष-वार आबंटित निधि तथा वर्ष 1998-99 की प्रथम छमाही में जारी निधि कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य 15-35 वर्ष की आयु वर्ग में 100 मिलियन निरक्षर व्यक्तियों को समयबद्ध ढंग से कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। साक्षरता अभियान इसकी प्रमुख कार्यनीति है। इस समय प्रौढ़ों में पूर्ण रूप से निरक्षरता उन्मूलन की समय-सीमा के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए वर्षवार क्रमशः 234.00 करोड़ रु०, 224.50 करोड़ रु० तथा 127.00 करोड़ रु० की निधियां आवंटित की गई। 30 सितम्बर, 1998 तक इन कार्यक्रमों के लिए 18.14 करोड़ रु० की निधियां आवंटित की गई हैं।

पूर्ण साक्षरता के लिए योजनाएं

2263. **श्री जर्नादन यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पूर्ण साक्षरता लाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की जा रही है;/कौन-कौन से उपाए किये जा रहे हैं;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से इस संबंध में कोई सहायता मिली है;